



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 465] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 12, 2017/अग्राहायण 21, 1939
No. 465] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 12, 2017/AGRAHAYANA 21, 1939

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

अधिसूचना

बड़ौदा, 15 नवम्बर, 2017

फा. सं. एचओ:एचआर- परि:ओएसआर & आईआर:282.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उपधारा (2) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बैंक ऑफ़ बड़ौदा का निदेशक मंडल भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श कर और केंद्र सरकार की पिछली मंजूरी के साथ, एतद्वारा बैंक ऑफ़ बड़ौदा ("अधिकारी") सेवा विनियम, 1979 में संशोधन करने के लिए आगे निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा:—

- (1) इन विनियमों को बैंक ऑफ़ बड़ौदा ("अधिकारी") सेवा (संशोधन) विनियम, 2017 के नाम से जाना जाएगा.
(2) इन विनियमों में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित हो, ये नवंबर, 2007 की पहली तारीख से प्रभावी समझे जाएंगे.
- बैंक ऑफ़ बड़ौदा ("अधिकारी") सेवा विनियम, 1979 (इसके पश्चात इन विनियमों के रूप में उल्लेखित) में, विनियम 3 में —

(i) उपखंड (एफ) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

‘(एफ) “परिवार” का अर्थ है अधिकारी का/की जीवनसाथी, पूर्ण रूप से आश्रित अविवाहित संतान (सौतेले बच्चों और कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चों सहित), 40 प्रतिशत या अधिक की विकलांगता वाले भाई या बहन, सामान्यतः अधिकारी के साथ रह रहे हों और उस पर पूर्ण रूप से आश्रित माता-पिता.’

स्पष्टीकरण- इस खंड के लिए बच्चे या माता-पिता या विकलांग भाई या बहन जिनकी मासिक आय रु. 3,500 से अधिक नहीं है उन्हें अधिकारी पर आश्रित समझा जाएगा.

परंतु यदि माता या पिता में से किसी एक की मासिक आय रु. 3,500 से अधिक होती है या माता-पिता की कुल मासिक आय रु. 3,500 से अधिक होती है, तो माता-पिता दोनों अधिकारी पर पूर्ण रूप से आश्रित नहीं समझे जाएंगे.

(ii) खंड (ओ) हटा दिया जाएगा.

3. उपरोक्त विनियमों के विनियम 4 में-

- i. उप-विनियम (4A) हटा दिया जाएगा.
- ii. इस प्रकार उप-विनियम (4A) हटा दिए जाने के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, यथा :-
 “(5) 1 नवंबर, 2007 से प्रभावी होने के साथ, प्रत्येक श्रेणी के लिए विनिर्दिष्ट वेतनमान निम्नानुसार होंगे:
 - a. उच्च कार्यपालक श्रेणी
 वेतनमान VII = रु. 46800 -1300/4 - 52000
 वेतनमान VI = रु. 42000-1200/4 - 46800
 - b. वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी
 वेतनमान V = रु. 36200-1000/2-38200-1100/2-40400
 वेतनमान IV = रु. 30600-900/4-34200-1000/2-36200
 - c. मध्य प्रबंधन श्रेणी
 वेतनमान III = रु. 25700 -800/5-29700-900/2-31500
 वेतनमान II = रु. 19400-700/1-20100 -800/10-28100
 - d. कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी
 वेतनमान I = रु. 14500-600/7-18700-700/2-20100-800/7-25700

स्पष्टीकरण : - इस वेतनमान द्वारा 31 अक्टूबर, 2007 तक शासित प्रत्येक अधिकारी को इस उप-विनियम में वर्णित वेतनमान में स्टेज टू स्टेज आधार पर 1 नवंबर, 2007 को फिट कर दिया जाएगा, अर्थात् संबंधित वेतनमान में प्रथम स्टेज के बाद से तदनुसूची स्टेज पर और अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित हो वेतनवृद्धियां सामान्यतः वार्षिक तिथि पर दी जाएंगी.

(6) इन सभी ग्रेडों में सेवा दे रहें अधिकारीगण के लिए, उप-विनियमों (1), (2), (3), (4) और (5) में ऐसा कुछ नहीं होगा जो बैंक के लिए हर समय अपेक्षित होगा.

4. उपरोक्त विनियमों के विनियम 5 में-

(a) उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1) 1 नवंबर, 2007 को एवं तब से विनियम 4 के उप-विनियम (5) के प्रावधानों के अधीन, वेतनवृद्धियां निम्नलिखित के अधीन मंजूर की जाएंगी, यथा:-

- (a) विनियम 4 के उप-विनियम (5) में निर्दिष्ट वेतनमान में वर्णित वेतनवृद्धियां, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अधीन होंगी, वार्षिक आधार पर प्राप्त होंगी और जिस महीने यह देय होगी उस महीने के पहले दिन मंजूर की जाएगी;
- (b) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान I के अधिकारी, जो उच्च वेतनमान के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II के वेतनमान में चले गए हैं, वे सेवाकाल का प्रत्येक तीन वर्ष पूर्ण करने के बाद चार अवरुद्ध वेतनवृद्धियों के लिए पात्र होंगे, जिनमें पहली दो वेतनवृद्धियां रु. 800/- एवं बाद की दो रु. 900/- होंगी:

परंतु कि जो अधिकारी दूसरी वेतनवृद्धि प्राप्त करने के बाद 1 नवंबर, 2007 को तीन वर्ष या इससे अधिक का समय पूरा कर चुके हैं, वे 1 नवंबर, 2007 को तीसरी अवरुद्ध वेतनवृद्धि प्राप्त करेंगे तथा दूसरी अवरुद्ध वेतनवृद्धि प्राप्त करने के बाद छः वर्ष पूर्ण करने पर 1 नवंबर, 2008 को या इसके बाद अन्य अवरुद्ध वेतनवृद्धि प्राप्त करेंगे.

- (c) मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II के अधिकारी, जो उच्च वेतनमान के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान III के वेतनमान में चले गए हैं, वे सेवाकाल का प्रत्येक तीन वर्ष पूर्ण करने के बाद रु. 900 प्रति वेतनवृद्धि के हिसाब से तीन अवरुद्ध वेतनवृद्धियों के लिए पात्र होंगे:

परंतु कि जो अधिकारी पहली वेतनवृद्धि प्राप्त करने के बाद 1 नवंबर, 2007 को तीन वर्ष या इससे अधिक का समय पूरा कर चुके हैं, वे 1 नवंबर, 2007 से अगली अवरुद्ध वेतनवृद्धि प्राप्त करेंगे तथा पहली अवरुद्ध वेतनवृद्धि के प्राप्त करने के बाद छः वर्ष पूर्ण करने पर 1 नवंबर, 2008 को या इसके बाद अन्य अवरुद्ध वेतनवृद्धि प्राप्त करेंगे।

परंतु यह कि मूल रूप से मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान III में नियुक्त या पदोन्नत हुए अधिकारी सेवाकाल का प्रत्येक तीन वर्ष पूरी करने के बाद रु. 900 प्रति वेतनवृद्धि के हिसाब से चार अवरुद्ध वेतनवृद्धियों के लिए पात्र होंगे या:

परंतु यह और कि वे अधिकारी, जो पहले ही दो अवरुद्ध वेतनवृद्धियां प्राप्त कर चुके हैं और 1 नवंबर, 2007 तक दूसरी वेतनवृद्धि प्राप्त करने के बाद सेवाकाल का तीन वर्ष से अधिक का समय पूर्ण कर चुके हैं, अपनी तीसरी वेतनवृद्धि 1 नवंबर, 2007 को तथा दूसरी अवरुद्ध वेतनवृद्धि प्राप्त करने के बाद छः वर्ष पूर्ण करने पर चौथी वेतनवृद्धि 1 नवंबर, 2008 को या उसके बाद प्राप्त करेंगे।

स्पष्टीकरण :- इस उप-विनियम के तहत अगले उच्च वेतनमान में ऐसी वेतनवृद्धियों की मंजूरी पदोन्नति के परिणामस्वरूप नहीं होंगी तथा उनके विशेषाधिकार, परिलब्धियां, कार्यदायित्व एवं उत्तरदायित्व मूल पदों के अनुसार जारी रहेंगी।

(b) उप-विनियम (2) में, -

(I) स्पष्टीकरण में, खंड (e) के बाद एवं नोट के पहले, निम्नलिखित खंड शामिल किया जाएगा, यथा:-

“(f) नवंबर, 2007 की पहली तारीख को एवं तब से, अन्य बातें एक समान रखते हुए, व्यावसायिक शैक्षणिक भत्ते की राशि निम्नानुसार संशोधित की जाएंगी:-

टेबल

जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक्स के जूनियर एसोसिएट्स ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक्स या सर्टिफाइड एसोसिएट्स ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक्स उत्तीर्ण कर चुके हैं।	(I) वेतनमान के उच्चतम स्तर पर पहुंच जाने के एक वर्ष बाद, रु. 410 प्रति माह.
जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक्स के सर्टिफाइड एसोसिएट्स के दोनों भाग उत्तीर्ण कर चुके हैं	(i) वेतनमान के उच्चतम स्तर पर पहुंच जाने के एक वर्ष बाद, रु. 410 प्रति माह. (ii) वेतनमान के उच्चतम स्तर पर पहुंच जाने के दो वर्ष बाद रु. 1030 प्रति माह.

परंतु कि वेतनमान के उच्चतम स्तर पर पहुंच जाने के बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक्स के जूनियर एसोसिएट्स ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक्स या सर्टिफाइड एसोसिएट्स ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक्स (कोई एक या दोनों भाग) की योग्यताएं प्राप्त करने वाला अधिकारी, ऐसी योग्यताएं प्राप्त करने की तारीख से व्यावसायिक योग्यता भत्ते की पहली किश्त प्राप्त करेगा तथा व्यावसायिक योग्यता भत्ते की बाद वाली किश्तें व्यावसायिक योग्यता भत्ते की जारी की गई पहली किश्त की तारीख के संदर्भ के साथ जारी की जाएंगी:

परंतु यह कि यदि अधिकारी ने पहले ही उपरोक्त में से कोई योग्यता प्राप्त कर ली है एवं ऐसी योग्यता प्राप्त करने के फलस्वरूप कोई वेतनवृद्धि या व्यावसायिक योग्यता भत्ता प्राप्त नहीं किया है, तो उसे 1 नवंबर, 2007 से या ऐसी योग्यता/ओं प्राप्त करने की तारीख से, जो भी बाद में हो, व्यावसायिक योग्यता भत्ता मंजूर किया जा सकता है।

(II) नोट में, खंड (v) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(v) यदि किसी अधिकारी ने, 27 अप्रैल, 2010 को खंड (iv) में संदर्भित उपरोक्त में से कोई योग्यता प्राप्त कर ली है एवं ऐसी योग्यता प्राप्त करने के फलस्वरूप कोई वेतनवृद्धि या व्यावसायिक योग्यता भत्ता प्राप्त नहीं किया है, तो उसे 1 नवंबर, 2007 से या ऐसी योग्यता/ओं प्राप्त करने की तारीख से, जो भी बाद में हो, व्यावसायिक योग्यता भत्ता मंजूर किया जा सकता है”।

सी) उप-विनियमन (3) में, -

(i) खंड (डी) के बाद और नोट से पहले, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(ई) 1 नवंबर 2007 को और तबसे और अन्य मामले समान होंगे, आवास किराया भत्ते के साथ नियत वैयक्तिक वेतन निम्नलिखित दरों पर होंगी और पूरी सेवा अवधि के लिए फ्रीज़ रहेंगी :-

टेबल

वेतनवृद्धि कम्पोनेंट (रु.)	वेतनवृद्धि कम्पोनेंट पर दिनांक 01.11.4007 तक महंगाई भत्ता (रु.)	देय कुल नियत वैयक्तिक वेतन जहां बैंक का आवास उपलब्ध कराया गया है (रु.)
(ए)	(बी)	(सी)
800	58	858
900	65	965
1000	72	1072
1100	79	1179
1200	86	1286
1300	94	1394",

(ii) नोट में खंड (i) और (ii) के लिए निम्नलिखित खंडों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(i) खंड (बी), (सी), (डी) या (ई) के तहत टेबल के कॉलम (सी) के तहत उल्लिखित अनुसार नियत वैयक्तिक भत्ता या नियत वैयक्तिक वेतन ऐसे अधिकारियों को देय होगा जिन्हें बैंक का आवास उपलब्ध कराया गया है.

(ii) आवास किराया भत्ता हेतु पात्र अधिकारियों के लिए नियत वैयक्तिक भत्ता या नियत वैयक्तिक वेतन खंड (ई) के तहत टेबल के कॉलम (ए) और (बी) के तहत निर्दिष्ट कुल राशि होगी और आ संबंधित अधिकारी कर्मचारी द्वारा आहारित आवास किराया भत्ता होगा, जब विनियम 4 के उप-विनियम (2), (3), (4) या (5) में विनिर्दिष्ट संबंधित वेतनमान की पिछली वेतनवृद्धि प्राप्त की है.

(iii) नोट के बाद प्रतिस्थापित खंड (ई) को इसके बाद उप-खंड (v) के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा और इसी क्रम के रूप में खंड (v) के लिए क्रमांकित किया जाएगा, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, अर्थात्:

"(v) जिस अधिकारी ने उपर्युक्त खंड (ए) के अनुसार अग्रिम वेतन वृद्धि प्राप्त की है, वे अधिकतम वेतनमान तक पहुँचने के एक वर्ष बाद उपर्युक्त खंड (बी), (सी), (डी) या (ई) में उल्लिखित अनुसार नियत वैयक्तिक भत्ता/ नियत वैयक्तिक वेतन का भाग आहरित कर सकते हैं.

5. उपरोक्त विनियमों के विनियमन 21 में, -

(i) उप-विनियमन (3) में, नोट को हटाया जाएगा;

(ii) उप-विनियमन (4) में, नोट को हटाया जाएगा;

(iii) उप-विनियमन (4) के बाद निम्नलिखित उप-विनियमन और नोट सम्मिलित किए जाएंगे, अर्थात्: -

"(5) 1 नवंबर, 2007 को और तब से, महंगाई भत्ता अखिल भारतीय औसत श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) आधार 1960=वेतन के 0.15% पर 100 की तिमाही औसत में 2836 अंकों पर चार अंकों की प्रत्येक वृद्धि या गिरावट के लिए देय होगा.

स्पष्टीकरण- इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए -

(ए) महंगाई भत्ते के उद्देश्य से "वेतन" का अर्थ है, अवरुद्धता वेतनवृद्धि के साथ मूल वेतन;

(बी) विनियम 5 के उप-विनियम (2) के लिए स्पष्टीकरण (सी), (डी), (ई) और (एफ) में विनिर्दिष्ट के रूप में व्यावसायिक शिक्षा भत्ता या व्यावसायिक शिक्षा वेतन को महंगाई भत्ता के लिए शामिल किया जाएगा'.

6. उप-विनियम (1) और (2) के लिए उपर्युक्त विनियमों के विनियमन 22 में निम्नलिखित उप-विनियमों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(1) 1 नवंबर, 2002 को और तब से,

(ए) जहां अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय आवास प्रदान किया जाता है, वहाँ अधिकारी जिस वेतनमान में है, उसके अपने वेतनमान के फ़र्स्ट स्टेज के मूल वेतन का 1.75 % के बराबर या आवास के लिए मानक किराया, जो भी कम हो, उससे वसूल किया जाएगा;

(बी) जहां अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय आवास उपलब्ध नहीं कराया जाता है, वह निम्नलिखित टेबल में विनिर्दिष्ट दरों पर आवास किराया भत्ता के लिए पात्र होगा, अर्थात्:

टेबल

	जिस वर्ग के अंतर्गत कार्यस्थल है	भुगतान किया जाने वाला एचआरए
	(1)	(2)
i)	प्रमुख "ए" वर्ग के नगर तथा समूह 'ए' के परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतनमान का 8.5%
ii)	क्षेत्र I में अन्य स्थान तथा समूह बी के परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतनमान का 7.5 %
iii)	अन्य स्थान	वेतनमान का 6.5 %

परंतु यह कि यदि कोई अधिकारी किराए की रसीद प्रस्तुत करता है तो उसे देय मकान किराया भत्ता, जिस वेतनमान में वह है उस वेतनमान के प्रथम स्टेज के वेतन के 1.75% से ऊपर, उसके द्वारा अपने आवास के लिए दिया गया वास्तविक किराया देय होगा अथवा ऊपर टेबल के कालम II में दर्शायी गयी दर से देय मकान किराया भत्ते का अधिकतम 150% देय होगा।

(2) 1 नवंबर 2007 को और तब से -

(ए) जहां अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय आवास प्रदान किया जाता है, वहाँ अधिकारी जिस वेतनमान में है, उस वेतनमान के फ़र्स्ट स्टेज के मूल वेतन का 1.20% के बराबर या आवास के लिए मानक किराया, जो भी कम हो, उससे वसूल किया जाएगा;

(बी) जहां अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय आवास उपलब्ध नहीं कराया जाता है, वह निम्नलिखित सारणी में निर्दिष्ट दरों पर आवास किराया भत्ता के लिए पात्र होगा, अर्थात्:

	जिस वर्ग के अंतर्गत कार्यस्थल है	भुगतान किया जाने वाला एचआरए
	(1)	(2)
i)	प्रमुख "ए" वर्ग के नगर तथा समूह 'ए' के परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतनमान का 8.5%
ii)	क्षेत्र I में अन्य स्थान तथा समूह बी के परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतनमान का 7.5 %
iii)	अन्य स्थान	वेतनमान का 6.5 %

परंतु यह कि यदि कोई अधिकारी किराए की रसीद प्रस्तुत करता है तो उसे देय मकान किराया भत्ता, जिस वेतनमान में वह है उस वेतनमान के प्रथम स्टेज के वेतन के 1.20% से ऊपर, उसके द्वारा अपने आवास के लिए दिया गया वास्तविक किराया देय होगा अथवा ऊपर कालम II में दर्शायी गयी दर से देय मकान किराया भत्ते का अधिकतम 150% देय होगा।

नोट- अधिकारी के मालिकाना आवास की लागत से लिंक आवास किराया भत्ता के लिए उनके दावों को अभी तक के आवास किराया भत्ता का 150 प्रतिशत तक सीमित किया जाएगा.";

7. उपरोक्त विनियमों के विनियम 23 में -

(i) उप-विनियम (1) में 1 नवंबर, 2002 के आंकड़े, अक्षरों और शब्दों को 1 नवंबर, 2007 के आंकड़े, अक्षरों और शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) उप-विनियम (1) में 1 नवंबर, 2002 के आंकड़े, अक्षरों और शब्दों के लिए 1 नवंबर, 2007 के आंकड़े, अक्षरों और शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा.

(iii) उप-विनियम (3), (4) और (5) के लिए निम्न उप-विनियमों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(3) 1 नवंबर, 2007 को और तबसे, यदि ग्रुप ए या ग्रुप बी में आने वाले परियोजना क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में कोई अधिकारी सेवा कर रहा है तो वह ग्रुप 'ए' या ग्रुप 'बी' के रूप में क्षेत्र के वर्गीकरण के अनुसार प्रति माह रु. 290 या प्रति माह रु. 255 की दर से परियोजना क्षेत्र क्षतिपूर्ति भत्ता के लिए पात्र होगा.

(4) 1 नवंबर, 2007 को और तबसे, यदि कोई अधिकारी किसी शैक्षणिक वर्ष के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता है और पिछले स्थान में स्कूल या कॉलेज में उनके एक या एक से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वह सभी बच्चों के लिए शैक्षणिक वर्ष के अंत तक दूसरे स्थान पर उसके रिपोर्ट करने की तारीख से प्रति माह रु. 700 का मध्य-शैक्षणिक वर्ष स्थानांतरण भत्ते के लिए पात्र होगा.

(5) 01 मई, 2010 को और तबसे यदि कोई अधिकारी बैंक के बाहर सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है, तो वह प्रतिनियुक्ति वाले पद से जुड़ी परिलब्धियों को प्राप्त करने का विकल्प चुन सकता है, या वह अपने वेतन के अतिरिक्त प्रति माह अधिकतम रु. 2300 के अधीन वेतन का 7.75 प्रतिशत की दर से प्रतिनियुक्ति भत्ता और ऐसे अन्य भत्ते जो बैंक की सेवा में उसके पद पर रहते हुए आहरित करता, आहरित कर सकता है :

परंतु कि उसे किसी ऐसे संगठन में तैनात किया गया है जहां वह उसी स्थान पर स्थित है जहां उन्हें अपने प्रतिनियुक्ति से तुरंत पहले तैनात किया गया था, तो उसे प्रति माह अधिकतम रु. 1200 के अधीन अपने वेतन के 4 प्रतिशत के बराबर प्रतिनियुक्ति भत्ता प्राप्त होगा.

परंतु कि एक संकाय सदस्य के रूप में बैंक के प्रशिक्षण प्रतिष्ठान में प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी प्रति माह अधिकतम रु. 1200 के अधीन अपने वेतन के 4 प्रतिशत के बराबर प्रतिनियुक्ति भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र होगा";

(iv) उप-विनियमन (8) के लिए, निम्न उप-नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(8) 1 नवंबर, 2007 को और तबसे, यदि किसी दिन के दौरान काम के घंटे को दो घंटों के न्यूनतम अंतराल में विभाजित किया गया है, तो अधिकारी प्रति माह रु. 165 की दर से स्प्लिट ड्यूटी भत्ता के लिए पात्र होगा.";

(v) उप-विनियमन (10) में, -

(ए) 1 नवंबर, 2002 के आंकड़े, अक्षरों और शब्दों को 1 नवंबर 2007 के आंकड़े, अक्षरों और शब्दों से प्रतिस्थापित किया गया है.

(बी) सारणी को निम्नलिखित सारणी से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"सारणी

	स्थान (1)	दर (2)
क)	1000 मीटर और उससे अधिक परंतु 1500 मीटर से कम ऊंचाई वाले स्थान और मेरकरा नगर	वेतन का 2 प्रतिशत अधिकतम 550/- प्रतिमाह
ख)	1500 मीटर और उससे अधिक परंतु 3000 मीटर से कम ऊंचाई वाले स्थान पर	वेतन का 2.5 प्रतिशत अधिकतम 680/- प्रतिमाह
ग)	3000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर	वेतन का 5 प्रतिशत अधिकतम 1570/- प्रतिमाह

8. उपरोक्त विनियमों के विनियम 24 में, उप-विनियम (1) में, खंड (ए) के लिए निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(ए) चिकित्सा व्यय - 1 नवंबर, 2007 को और तबसे अधिकारी एवं उसके परिवार के चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति संबंधित अधिकारी के प्रमाण-पत्र के आधार पर की जा सकती है जिसमें निम्नलिखित टेबल में विनिर्दिष्ट अनुसार ऐसे खर्चों के व्यौरे के साथ दावा की गई राशि का लेखा विवरण भी होता है अर्थात्:-

टेबल

श्रेणी	प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा
कनिष्ठ प्रबंधन और मध्य प्रबंधन श्रेणी	रु. 5100 या अदत्त राशि जो भी कम है
वरिष्ठ प्रबंधन और उच्च कार्यपालक श्रेणी	रु. 6320 या अदत्त राशि जो भी कम है

नोट- (i) अधिकारी को प्राप्त नहीं की गई चिकित्सा सहायता को संचय करने की अनुमति होगी ताकि यह उपरोक्त उपलब्ध कराई गई अधिकतम राशि से किसी भी समय तीन गुना अधिक न हो;

(ii) वर्ष 2007 के लिए चिकित्सा सहायता योजना के तहत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति दो महीने, अर्थात् नवंबर 2007 और दिसंबर 2007 के लिए आनुपातिक रूप से बढ़ा दी जाएगी.

स्पष्टीकरण - इस विनियम के प्रयोजनों के लिए -

(i) अधिकारी के मामले में जहां हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता होती है, हॉस्पिटलाइजेशन प्रभार 100 प्रतिशत और अपने परिवार के सदस्यों के सभी मामलों में 75 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की जाएगी;

(ii) 1 मई, 2010 को और तबसे इस विनियमन के तहत हॉस्पिटलाइजेशन व्ययों की प्रतिपूर्ति, निम्नलिखित टेबल में विनिर्दिष्ट सीमाओं के अधीन कामगार कर्मचारियों के लिए दिनांक 27 अप्रैल 2010 के द्विपक्षीय समझौते के तहत निर्धारित हॉस्पिटलाइजेशन योजना के नियमों और शर्तों के अनुसार होगी, अर्थात्:-

टेबल

(ए) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान I और मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II और III	<p>(i) बेड प्रभार</p> <p>स्वयं – रु. 700 प्रति दिन</p> <p>परिवार – रु. 525 प्रति दिन</p> <p>(ii) अन्य प्रभार</p> <p>कामगार कर्मचारियों के लिए लागू हॉस्पिटलाइजेशन योजना के तहत निर्धारित सीमाओं के 125% के वेतनमान पर.</p>
(बी) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान IV और V और उच्च कार्यपालक श्रेणी वेतनमान VI और VII	<p>(i) बेड प्रभार</p> <p>स्वयं – रु. 900 प्रति दिन</p> <p>परिवार – रु. 675 प्रति दिन</p> <p>(ii) अन्य प्रभार</p> <p>कामगार कर्मचारियों के लिए लागू हॉस्पिटलाइजेशन योजना के तहत निर्धारित सीमाओं के 150% के वेतनमान पर.</p>

9. उपरोक्त विनियमों के विनियम 25 में, उप-विनियम (2) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(2) उप-विनियमन (1) में निहित कुछ भी होने के बावजूद, 01 नवंबर 2007 को और तब से जिस वेतनमान में अधिकारी है उस वेतनमान के प्रथम स्टेज के मूल वेतन के 1.20% के बराबर या आवास के लिए मानक किराया, जो भी कम हो, उसके लिए बैंक के पास यह विकल्प होगा कि अधिकारी द्वारा भुगतान करने पर अधिकारी को आवास प्रदान करे.

परंतु कि जहां अधिकारी को ऐसा आवास फर्नीचर के साथ दिया जाता है, वहाँ जिस वेतनमान में वह है उस वेतनमान के प्रथम स्टेज के मूल वेतन के 0.25% के बराबर उससे बैंक द्वारा वसूल किया जाएगा:

परंतु यह भी कि जहां ऐसे आवासीय आवास बैंक द्वारा प्रदान किए जाते हैं, वहाँ बिजली, पानी, गैस और सफाई-व्यवस्था के लिए प्रभार अधिकारी द्वारा वहन किया जाएगा."

10. उपरोक्त विनियमों के विनियमन 36 में, उप-विनियमन (2) के बाद निम्नलिखित उप-विनियमन समायोजित की जाएगी, अर्थात्: -

"(3) 1 मई, 2010 से 12 महीने की अधिकतम अवधि के भीतर हिस्टेरेक्टोमी के मामले में अधिकतम 45 दिन की छुट्टी भी दी जा सकती है."

11. उपरोक्त विनियमों के विनियम 41 में, उप-विनियम (4) में, खंड (a) के स्थान पर निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

'(a) विराम भत्ता - मई, 2010 के पहले दिन को एवं तब से निम्न टेबल के कॉलम (1) में वर्णित श्रेणियों या वेतनमानों का अधिकारी इसके कॉलम (2) में वर्णित तदनुसूची दरों पर 'दैनिक' विराम भत्ता हेतु पात्र होगा:-

टेबल

अधिकारियों की श्रेणियां/वेतनमान	मेजर 'A' क्लास के शहर	क्षेत्र - I	अन्य स्थान
(1)	(2)		
	रु.	रु.	रु.
वेतनमान IV और उससे ऊपर के अधिकारी	1000	800	700
वेतनमान I/II/III के अधिकारी	800	700	600

परंतु वेतनमान IV और उससे ऊपर के अधिकारियों के मामले में, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई इन चार महानगरों में बाहरी कार्य के समय देय दैनिक विराम भत्ता रु. 1200 होगा और वेतनमान I या II या III के अधिकारियों के लिए दैनिक विराम भत्ता रु. 1000 होगा:

परंतु यह कि जहां अनुपस्थिति की अवधि 8 घंटे से कम पर 4 घंटे से अधिक है, देय विराम भत्ता उपरोक्त दरों का आधा होगा.

स्पष्टीकरण:- विराम भत्ते की गणना के लिए, 'दैनिक' का अर्थ 24 घंटे की प्रत्येक अवधि और इसके बाद का कोई भाग होगा, हवाई यात्रा के मामले में प्रस्थान के लिए रिपोर्ट करने का समय तथा अन्य मामलों में प्रस्थान के लिए निर्धारित समय से लेकर आगमन के वास्तविक समय तक माना गया है तथा जहां अनुपस्थिति की अवधि 24 घंटों से कम है, "दैनिक" का अर्थ 8 घंटे की अवधि से कम नहीं होगा.

12. उपरोक्त विनियमों के विनियम 42 में, उप-विनियम (3) के बाद निम्नलिखित उप विनियम को शामिल किया जाएगा, यथा:-

"4 मई, 2010 के पहले दिन को एवं तब से, अधिकारी के स्थानांतरण होने पर, वह पैकिंग, स्थानीय ट्रांसपोर्टेशन, सामानों का बीमा कराने आदि के संबंध में निम्न टेबल में निर्धारित किए गए अनुसार एक मुश्त राशि आहरित करने का पात्र होगा, यथा:-

टेबल

श्रेणी	एक मुश्त राशि
उच्च कार्यपालक एवं वरिष्ठ प्रबंधन	रु. 12,000
मध्य प्रबंधन एवं कनिष्ठ प्रबंधन	रु. 9,000

13. उपरोक्त विनियमों के विनियम 44 में, उप-विनियम (3) के बाद निम्नलिखित परंतुक को शामिल किया जाएगा, यथा:-

परंतु कि 1 मई, 2010 से, कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान I का अधिकारी छुट्टी यात्रा रियायत प्राप्त करते समय न्यूनतम भाड़ा इकोनॉमी क्लास में हवाई यात्रा करने का पात्र होगा और इस मामले में तय की गई दूरी के लिए वास्तविक किराए या ट्रेन से एसी प्रथम श्रेणी को लागू किराए, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जाएगी और यही नियम 1000

कि.मी से कम की दूरी के लिए छुट्टी यात्रा रियायत प्राप्त करते समय मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II और वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान III के अधिकारी को लागू होगा।

14. उपरोक्त विनियमों के विनियम 45 में,

(i) उप-विनियम (1) के बाद निम्नलिखित परंतुक को शामिल किया जाएगा, यथा:-

“परंतु अप्रैल, 2010 की पहली तारीख को या इसके बाद बैंक की सेवा में नियुक्त अधिकारियों के लिए कोई भविष्य निधि नहीं होगी.”

(ii) उप-विनियम (3) में, खंड (b) के बाद और नोट के पहले निम्नलिखित खंड शामिल किया जाएगा, यथा:-

“(c) अंशदायी भविष्य निधि योजना के तहत कवर किए गए अधिकारी, जिन्होंने पेंशन योजना का विकल्प नहीं लिया है, अंशदायी भविष्य निधि योजना के तहत रहेंगे.”

(iii) उप-विनियम (3) के बाद निम्नलिखित उप-विनियम को शामिल किया जाएगा, यथा:-

“4 अप्रैल, 2010 की पहली तारीख को या इसके बाद बैंक की सेवा में नियुक्त अधिकारी परिभाषित अंशदायी भविष्य निधि योजना के द्वारा कवर किए जाएंगे, जिसमें समय-समय पर संशोधित, भारत सरकार की अधिसूचना, एफ. नं. 5/7/2003-ईसीबी एंड पीआर दिनांक 22 दिसंबर, 2003 के द्वारा केंद्र सरकार द्वारा न्यू पेंशन स्कीम के अनुसार, अंशदायी भविष्य निधि योजना के प्रावधानों के अनुरूप, अधिकारी अपने वेतन + महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान करेगा और बैंक इसके बराबर की राशि का अंशदान करेगा।

15. उपरोक्त विनियमों की अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(अधिकारी) विनियमन, 1979 हेतु अनुसूची

(विनियम 23 का उप-विनियम (2) देखें)

नवंबर, 2007 के पहले दिन से, निम्न टेबल में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार, अधिकारी उस समय तक विशेष क्षेत्र भत्ते के लिए पात्र होंगे जब तक कि इसे समाप्त नहीं लिया जाता या पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से संशोधित नहीं किया जाता, यथा:-

टेबल

क्र.सं.	क्षेत्र	भत्ता (₹)	
		₹14,700/- से कम वेतनमान	₹14,700/- से अधिक वेतनमान
1	2	3	4
1.	मिज़ोरम (ए) मिज़ोरम का चमटुईपुई जिला तथा मिज़ोरम के लुंगलेई जिले के लुंगलई शहर से 25 किमी से अधिक दूरी वाले क्षेत्र	2000	2600
	(बी) पूरे लुंगलेई जिले में, मिज़ोरम के लुंगलेई शहर से 25 किमी से दूर वाले क्षेत्र छोड़कर	1600	2100
	(सी) मिज़ोरम का पूरा आइजौल जिला	1200	1500
2.	नागालैंड	1600	2100
3.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह (ए) उत्तरी और मध्य अंदमान, लघु अंदमान, निकोबार और नार्कोडम द्वीप समूह (बी) दक्षिण अंदमान (पोर्ट ब्लेयर सहित)	2000 1600	2600 2100
4.	सिक्किम	2000	2600

क्र.सं.	क्षेत्र	भत्ता (₹)	
		₹14,700/- से कम वेतनमान	₹14,700/- से अधिक वेतनमान
1	2	3	4
5.	लक्षद्वीप समूह	2000	2600
6.	असम	320	400
7.	मेघालय	320	400
8.	त्रिपुरा		
	(ए) त्रिपुरा के कठिन क्षेत्र	1600	2100
	(बी) कठिन क्षेत्रों को छोड़कर पूरा त्रिपुरा	1200	1500
9.	मणिपुर	1200	1500
10.	अरुणाचल प्रदेश		
	(ए) अरुणाचल प्रदेश के कठिन क्षेत्र	2000	2600
	(बी) कठिन क्षेत्र के अलावा समस्त अरुणाचल प्रदेश	1600	2100
11.	जम्मू और कश्मीर		
	ए) कठुआ जिला :	2000	2600
	नियाबत बानी, लोही, मलहार, मछोड़ी		
	बी) उधमपुर जिला :		
	(i) दादू बसंतगढ़, लेंडर भमाग इलाका, भाग 2(बी) में समाहित को छोड़कर	2000	2600
	(ii) कम्बन की ओर से गोयल तथा तहसील मोहरे में केयसी से अरदास तक के क्षेत्र	1600	2100
	(सी) डोडा जिला:		
	पाडेर के इलाके और किश्तवार तहसील में नियाबत नौगाम	2000	2600
	(डी) लेह जिला:		
	जिले के सभी स्थान	2000	2600
	(ई) बारामुला जिला :		
	(i) समस्त गुरेज-निराबत, तंगदार सब डिविजन तथा केरन इलाका	2000	2600
	(ii) मचिल	1600	2100
	(एफ़) पुंछ तथा राजौरी जिला:		
	पुंछ और राजौरी नगरों को छोड़कर पुंछ और राजौरी के अन्य क्षेत्र तथा दोनों जिलों के सुंदरबनी तथा अन्य शहरी क्षेत्र	1200	1500
	(जी) मद सं, ए से एफ में शामिल नहीं है, परंतु जो वास्तविक लाइन ऑफ़ कंट्रोल या ऐसे किसी स्थान से 8 कि.मी. के अंतर के अंतर्गत है, जिसे राज्य सरकार अपने स्टाफ सदस्यों के लिए समय-समय पर बॉर्डर भत्ते के रूप में पात्र घोषित करती है.	1200	1500

12.	हिमाचल प्रदेश (ए) चंबा जिला (i) पांगी तहसील, भरमौर तहसील, पंचायतें: बड़गांव, बाजोल, देवल कुग्ती, नयागाम और टुंडा, गांव: ग्राम पंचायत जगत का घाटू, ग्राम पंचायत चौहटा का कनारसी (ii) उपरोक्त (i) मद में समाहित गांवों और पंचायत को छोड़कर भरमौर जिला	2000 1600	2600 2100
	(iii) भलियाट तहसील में झंडरू पंचायत, चुराह तहसील, डलहौसी टाउन (मूल बानीखेत सहित)	1200	1500
	(बी) किन्नौर जिला: (i) असरंग, चितकुल और हंगोकुनो/चारंग पंचायत, छोटा खंबा, नथपा, और रूपी की ग्राम पंचायतों को सम्मिलित करते हुए 15/20 क्षेत्र, पूह उप विभाग, उपरोक्त निर्धारित पंचायत क्षेत्र को छोड़कर (ii) उपरोक्त (क) में सम्मिलित क्षेत्रों को छोड़कर समग्र जिला	2000 1600	2600 2100
	(सी) कुल्लू जिला: (i) खरगा, कुश्वर और सर्गा की ग्रामपंचायतों को सम्मिलित करते हुए निर्मद तहसील के 15/20 क्षेत्र (ii) बाहरी-सेरज (निर्मद तहसील के जकात खाना और बरों गांवों को छोड़कर) और संपूर्ण जिला बाहरी सेरज क्षेत्र और पंडरबीस के परगना को छोड़कर परंतु तहसील निर्मद के जगत खाना और बरों को सम्मिलित करते हुए) (डी) लाहौल और स्पिति जिला : लाहौल और स्पिति जिला का संपूर्ण क्षेत्र (ई) शिमला जिला : (i) कूट, लबाना-सादना, सरपरा और चड़ी बरान्दा की पंचायतों को सम्मिलित करते हुए रामपुर तहसील के 15/20 क्षेत्र	2000 1200 2000 2000	2600 1500 2600 2600

	(ii) दोरा-कवर तहसील, रामपुर में दारकली की ग्राम पंचायत और मुनीश, परगना सराहन की घोरी चौबीस	1600	2100
	(iii) चोपाल तहसील और घोरीस, पंजगांव, परगना साराह की पतखौ, नौबीस और तीन कोटी, तकलेश क्षेत्र की देओठी ग्राम पंचायत, परगना बाराबीस, रामपुर तहसील की परगना रामपुर के कस्बा रामपुर और घोरी नोग, शिमला टाउन और उसके नगर परिसर (ढल्ली, जटोग, कसूमि, माशोबरा, तारादेवी और टुट्ट)	1200	1500
	(एफ़) कांगड़ा जिला: (i) बारा भांगल और छोटा भांगल के क्षेत्र	1600	2100

	(ii) कांगड़ा जिले की धरमशाला टाउन और म्युनिसिपल सीमा के बाहर परंतु धरमशाला में सम्मिलित स्थित निम्न कार्यालय: टाउन वुमेंस आईटीआई, दारी, मिक्केनिकल वर्कशॉप, रामनगर, चाइल्ड वेलफेयर और टाउन और कंट्री प्लानिंग कार्यालय, साकोह, लोवर साकोह की सीआरएसएफ कार्यालय, कांगरा मिल्क सप्लाय योजना, डुगैर, एचाअरटीसी वर्कशॉप, साधेर, जोनल मलेरिय कार्यालय, दारी, फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन कार्यालय, शामनगर, टी फैक्टरी, दारी, आईपीएच उपविभाग, दान, सेटलमेंट कार्यालय, शामनगर, बिनवा प्रोजेक्ट, शामनगर, एचपीकेवीवी कैम्पस, पालमपुर सहित कांगरा जिले का पालमपुर टाउन, और म्युनिसिपल सीमा के बाहर परंतु पालमपुर टाउन में सम्मिलित स्थित निम्न कार्यालय: एचपी त्रिष विश्वविद्यालय कैम्पस, कैटल डेवेलपमेंट कार्यालय/जर्सी फार्म, बनौरी, सेरिकल्चर कार्यालय/इंडो जर्मन एग्रीकल्चर वर्कशॉप/ एचपीपीडबल्यूडी डिविजन, इलेक्ट्रिकल सब डिविजन, लोहना, डीपीओ कॉर्पोरेशन, बुंदला, इलेक्ट्रिकल एचपीएसईई डिविजन, घुग्गर	1200	1500
	(जी) मंडी जिला: जोगिंदरनगर की छुहर वैली, बागरा तहसील के थुनाग की पंचायतें, चातरी, छोटधर, गारगुदसहिन, गाढ़ू, गरयास, जनजेहली, जरयार, जोहर, कलहानी, कलवान, खोलनाल, लोथ, सिल्लीबागी, सोमाचन, थाचधर, ताची, थाना, धरमपुर, ब्लॉक-बोंगा की पंचायतें, कामलाह, सकलाना, तन्यार और ताराखोलह, तहसील बलीधर की करसोग की पंचायतें, बागरा, गोपालपुर, खाजोल, महोग, मेहूडी, मंज, पेखी, सेंज, साराहन और तेवान, सुंदरनगर तहसील-बोही की पंचायतें, बटवारा, धन्यारा, पौरा कोठी, सेरी और शोजा	1200	1500
	(एच) सिरमौर जिला: बानी, बाखली (पाचड़ तहसील), भारोग भेनारी (पाओंता तहसील), बिरला (नाहन तहसील), डिव्वर (पाछड़ तहसील) और थाना कासोगा (नाहन तहसील) की पंचायतें और थांसगिरी ट्रैक्ट	1200	1500
	(आई) सोलन जिला : मंगल पंचायत	1200	1500
	(जे) उपरोक्त मद (ए) से (i) में साम्मिलित नहीं किए गए हिमाचल प्रदेश के अन्य क्षेत्र	320	400
13.	उत्तराखंड चमोली, पिथोरगढ और उत्तर काशी, रुद्रप्रयाग और चांपावत जिलों के तहत आने वाले क्षेत्र	2000	2600"

व्याख्यात्मक ज्ञापन

यह विनियम जिन्हें पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया है, इस संबंध में संबंधित बैंकों और शीर्ष स्तरीय कामगार यूनियनों तथा बैंकों के अधिकारी संघों द्वारा दिए गए विशेष अधिदेश के आधार पर सदस्य बैंकों की ओर से भारतीय बैंक संघ के बीच हस्ताक्षर किए गए समझौतों और संयुक्त नोट के सहमत नियम एवं शर्तों के अनुसार है. अतः इस तरह के पूर्वव्यापी प्रभाव से किसी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा

के. बी. गुप्ता, महा प्रबंधक प्रमुख (मानव संसाधन परिचालन)

[विज्ञापन III/4/असा./327/17]

नोट: मूल विनियम दिनांक को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा इसके बाद संशोधित किए गए थे, यथा :—

1. नं. _____, दिनांक _____
- 2.
- 3.

BANK OF BARODA

NOTIFICATION

Baroda, the 15th November, 2017

F. No. HO: HR-OPS:OSR&IR:282.—In exercise of the powers conferred by section 19, read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the Bank of Baroda,

in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend Bank of Baroda (Officers') Service Regulations, 1979, namely: -

1. (1) These regulations may be called the Bank of Baroda, (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2017.
(2) They shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of November, 2007, except as otherwise provided in these regulations.
2. In the Bank of Baroda, (Officers') Service Regulations, 1979 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 3,-

- (i) for clause (f), the following clause shall be substituted, namely:-

‘(f) “family” means the spouse of the officer, wholly dependent unmarried children (including step children and legally adopted children), physically challenged brother or sister with forty per cent, or more disability and parents ordinarily residing with and wholly dependent on the officer’.

Explanation.- For the purposes of this clause a child or parent or physically challenged brother or sister shall be deemed to be dependent on the officer if the monthly income of such child, parent, brother or sister does not exceed Rs.3,500 per month.

Provided that if the income of one of the parents exceeds Rs.3,500 per month or the aggregate income of both the parents exceeds Rs.3,500 per month, both the parents shall not be considered as wholly dependent on the officer.’

- (ii) Clause (o) shall be omitted.

3. In regulation 4 of the said regulations,-

- (i) sub-regulation (4A) shall be omitted;

- (ii) after sub-regulation (4A) as so omitted, the following sub-regulations shall be inserted, namely:-

“(5) With effect from the 1st November, 2007, the scales of pay specified against each grade shall be as under :

- (a) Top Executive Grade

Scale VII = Rs.46800 – 1300/4 – 52000

Scale VI = Rs.42000 - 1200/4 – 46800

- (b) Senior Management Grade

Scale V = Rs.36200 – 1000/2 – 38200 – 1100/2 - 40400

Scale IV = Rs.30600 – 900/4 – 34200– 1000/2 – 36200

- (c) Middle Management Grade

Scale III = Rs.25700 - 800/5— 29700 - 900/2 - 31500

Scale II = Rs.19400 - 700/1 - 20100 -800/10 - 28100

- (d) Junior Management Grade

Scale I = Rs.14500-600/7- 18700-700/2- 20100- 800/7-25700.

Explanation.—Every officer who is governed by the scales of pay in force as on the 31st October, 2007 shall be fitted in the scale of pay set out in this sub-regulation as on 1st November, 2007 on stage to stage basis, i.e. on corresponding stages from first stage onwards in the respective scales and the increments shall fall on the anniversary date as usual except where provided otherwise.

- (6) Nothing in sub-regulations (1), (2), (3), (4) and (5) shall be construed as requiring the Bank to have at all times, officers serving in all these grades.”.

4. In regulation 5 of the said regulations, -

- (a) for sub-regulation (1), the following sub-regulation, shall be substituted, namely: -

“(1) Subject to the provisions of sub-regulation (5) of regulation 4, on and from the 1st November, 2007, the increments shall be granted subject to the following, namely: -

- (a) the increments specified in the scales of pay set out in sub-regulation (5) of regulation 4 shall, subject to the sanction of the Competent Authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due;
- (b) officers in Junior Management Grade Scale I who have moved to scale of pay for Middle Management Grade Scale II after reaching maximum of the higher scale shall be eligible for four stagnation increments for every three completed years of service of which first two shall be Rs.800 each and next two Rs.900 each:

Provided that officers who have completed three years or more after receipt of the second stagnation increment as on 1st November, 2007 shall get the third stagnation increment on 1st November, 2007 and another stagnation increment on or after the 1st November, 2008 on their completion of six years after receipt of second stagnation increment;

- (c) officers in Middle Management Grade Scale II who have moved to scale of pay for Middle Management Grade Scale III after reaching maximum of higher scale shall be eligible for three stagnation increments of Rs.900 each for every three completed years of service:

Provided that officers who have completed three years or more after receipt of the first stagnation increment as on the 1st November, 2007 shall get the next stagnation increment with effect from the 1st November, 2007 and a subsequent stagnation increment on or after the 1st November, 2008 on their completion of six years after receipt of the first stagnation increment:

Provided further the officers appointed to or promoted in substantive Middle Management Grade Scale III, shall be eligible for four stagnation increments of Rs.900 each for every three completed years of service or :

Provided also that the officers who have already received two stagnation increments and completed more than three years of service after receipt of second stagnation increment as on the 1st November, 2007 shall get the third stagnation increment on the 1st November, 2007 and the fourth stagnation increment, on or after the 1st November, 2008 on completion of six years after receipt of second stagnation increment.

Explanation.— Grant of such increments in the next higher scale under this sub-regulation shall not amount to promotion and the privileges, perquisites, duties and responsibilities of the officers shall continue as of their substantive posts.

- (b) in sub-regulation (2),-

- (i) in the Explanation, after clause (e) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely:-

“(f) on and from the 1st day of November, 2007, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Pay shall stand revised as under:-

TABLE

Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs. 410 per month one year after reaching maximum of the Scale.
Those who have passed both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs.410 per month after one year on reaching maximum of the Scale. (ii) Rs.1030 per month after two years on reaching maximum of the Scale;

Provided that an Officer acquiring Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers (either or both parts) qualifications after reaching the maximum of the scale of pay, shall be granted from the date of acquiring such qualification the first installment of Professional Qualification Pay and the release of subsequent installments of Professional Qualification Pay shall be with reference to the date of release of first installment of Professional Qualification Pay:

Provided further that in a case where an officer, has already acquired any of the above qualifications and has not earned any increment or Professional Qualification Pay on account of acquiring such qualification, he may be granted the Professional Qualification Pay, with effect from the 1st November 2007 or the date of acquiring such qualification/s, whichever is later.”;

(ii) in the Note, for clause (v), the following clause shall be substituted, namely:-

“(v) if an officer, as on the 27th April 2010 has already acquired any of the said qualifications referred to in clause (iv) and has not earned any increment or Professional Qualification Pay on account of acquiring such qualification, he shall be granted the Professional Qualification Pay, with effect from the 1st day of November, 2007 or the date of acquiring such qualification, whichever is later.”;

(c) in sub-regulation (3),-

(i) after clause (d) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely:-

“(e) on and from the 1st November, 2007, other things being equal, Fixed Personal Pay together with House Rent Allowance shall be at the following rates and shall remain frozen for the entire period of service:-

TABLE

Increment Component (Rs.)	Dearness Allowance as on 01.11.2007 on the increment components (Rs.)	Total Fixed Personal Pay payable where bank's accommodation is provided (Rs.)
(A)	(B)	(C)
800	58	858
900	65	965
1000	72	1072
1100	79	1179
1200	86	1286
1300	94	1394”

(ii) in the Note, for clauses (i) and (ii), the following clauses shall be substituted, namely:-

“(i) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay as indicated under column (C) of the Table under clauses (b), (c), (d) or (e) shall be payable to those officers who are provided with bank's accommodation.

(ii) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay for officers eligible for House Rent Allowance shall be the aggregate amount specified under columns (A) and (B) of the Table under clause (e) and House Rent Allowance drawn by the concerned officer employees when the last increment of the relevant scale of pay as specified in sub-regulations (2), (3), (4) or (5) of regulation 4 is earned.”;

(iii) clause (e) occurring after the Note shall be renumbered as sub-clause (v) thereof and for clause (v) as so numbered, the following clause be substituted, namely:-

“(v) An officer who has earned the advance increment as in clause (a) above shall draw the quantum of Fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay as mentioned in clauses (b), (c), (d) or (e) above, one year after reaching the maximum of the scale”;

5. In regulation 21 of the said regulations, -

(i) in sub-regulation (3), the Note shall be omitted;

(ii) in sub-regulation (4), the Note shall be omitted;

(iii) after sub-regulation (4), the following sub-regulation and Note shall be inserted, namely:-

- “(5) On and from the 1st day of November, 2007, dearness allowance shall be payable for every rise or fall of four points over 2836 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960=100 at 0.15% of Pay.

Explanation.- For the purposes of this sub-regulation,-

- (a) “pay” for the purpose of Dearness Allowance shall mean basic pay including Stagnation Increments;
- (b) Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay as specified in Explanations (c), (d), (e) and (f) to sub-regulation (2) of regulation 5 shall rank for dearness allowance’.

6. In regulation 22 of the said regulations, for sub-regulations(1) and (2), the following sub-regulations shall be substituted, namely:-

“(1) on and from the 1st day of November, 2002,

- (a) where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 1.75 per cent of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, shall be recovered from him;
- (b) where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the rates specified in the following table, namely:

TABLE

Where the place of work is in	HRA payable shall be
(1)	(2)
(i) Major “A” Class Cities and Project Area Centres in Group A	8.5% of Pay
(ii) Other places in Area I and Project Area Centres in Group B	7.5% of Pay
(iii) Other places	6.5% of Pay:

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for the residential accommodation in excess over 1.75 per cent of pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed with a maximum of 150 per cent of the House Rent Allowance payable as per column (2) of the above Table.

(2) on and from the 1st day of November, 2007, -

- (a) where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 1.20 per cent of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, shall be recovered from him;
- (b) where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the rates specified in the following table, namely: -

TABLE

Where the place of work is in	HRA payable shall be
(1)	(2)
(i) Major “A” Class Cities and Project Area Centres in Group A	8.5% of Pay
(ii) Other places in Area I and Project Area Centres in Group B	7.5% of Pay
(iii) Other places	6.5% of Pay

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for the residential accommodation in excess over 1.20 per cent of Pay in the first stage of the Scale of Pay in which he is placed with a maximum of 150 per cent of the House Rent Allowance payable as per aforesaid rates mentioned in column (2) above.

Note.—The claims of officers for House Rent Allowance linked to the cost of their ownership accommodation shall also be restricted to 150 per cent of House Rent Allowance as hitherto.”;

7. In regulation 23 of the said regulations,-

- (i) in sub-regulation (1), for the figures, letters and words “1st day of November 2002”, the figures, letters and words “1st day of November 2007” shall be substituted;
- (ii) in sub-regulation (2), for the figures, letters and words “1st day of November 2002, the figures, letters and words “1st day of November 2007” shall be substituted;
- (iii) for sub-regulations (3), (4) and (5), the following sub-regulations shall be substituted, namely:-

“(3) On and from the 1st day of November, 2007, if an officer is serving in an area to be specified as Project Area falling in Group A or Group B, he shall be eligible for a Project Area Compensatory Allowance at the rate of Rs.290 per month or Rs.255 per month according to the classification of area as Group A or Group B.

(4) On and from the 1st day of November, 2007, if an officer is transferred from one place to another in the midst of an academic year and if he has one or more children studying in school or college, in the former place, he shall be eligible for a mid-academic year transfer allowance of Rs.700 per month from the date he reports to the latter place upto the end of the academic year in respect of all the children, provided that such allowance shall cease if all the children cease studying at the former place.

(5) On and from the 1st day of May, 2010, if an officer is deputed to serve outside the Bank, he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed, or he may in addition to his pay, draw a deputation allowance at the rate of 7.75 per cent of pay subject to a maximum Rs.2300 per month and such other allowances he would have drawn had he been posted in the Bank’s service at that place:

Provided that where he is deputed to an organisation which is located at the same place where he was posted immediately prior to his deputation, he shall receive a deputation allowance equal to 4 per cent of his pay subject to a maximum Rs.1200 per month:

Provided further that an officer on deputation to the Training Establishment of the Bank as a faculty member shall be eligible for deputation allowance at the rate of 4 per cent of his pay subject to a maximum Rs.1200 per month.”;

- (iv) for sub-regulation (8), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(8) on and from the 1st day of November 2007, if the working hours during a day are split with minimum interval of two hours, an officer shall be eligible for a Split Duty Allowance at the rate of Rs.165 per month.”;

- (v) in sub-regulation (10),-

(a) for the figures, letters and words “1st day of November 2002”, the figures, letters and words “1st day of November, 2007” shall be substituted;

(b) for the Table, the following Table shall be substituted, namely:-

“TABLE

Place	Rate
(1)	(2)
(i) Place with an altitude of 1000 metres and above but less than 1500 metres and Mercara Town	2% of pay subject to a maximum of Rs. 550 per month
(ii) Place with an altitude of 1500 metres and above but less than 3000 metres	2½% of pay subject to a maximum of Rs. 680 per month
(iii) Place with an altitude of 3000 metres and above	5% of pay subject to a maximum of Rs. 1570 per month”;

8. In regulation 24 of the said regulations, in sub-regulation (1), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

“(a) Medical Expenses.- On and from the 1st day of November 2007, an officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses for self and family on the strength of the officer’s own certificate of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed as specified in the table below, namely:-

TABLE

Grade	Maximum limit of reimbursement
Junior Management and Middle Management Grade	Rs. 5100 or the amount incurred whichever is less
Senior Management and Top Executive Grade	Rs. 6320 or the amount incurred whichever is less

Note.- (i) an officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above or;

(ii) for the year 2007, the reimbursement of medical expenses under the medical aid scheme shall be enhanced proportionately for two months, that is, November 2007 and December 2007.

Explanation. - for the purposes of this regulation,-

- (i) hospitalisation charges shall be reimbursed to the extent of 100 per cent in the case of an officer and 75 per cent, in the case of his family members in respect of all cases which require hospitalization or;
- (ii) on and from the 1st day of May, 2010, reimbursement of hospitalisation expenses under this regulation shall be in accordance with the terms and conditions of Hospitalisation Scheme as laid down under the Bipartite Settlement dated the 27th day of April, 2010 for workmen employees, subject to the limits as specified in the table below, namely:-

TABLE

(a) Junior Management Grade Scale I and Middle Management Grade Scales II and III.	<p>(i) Bed Charges</p> <p>Self – Rs. 700 per day</p> <p>Family – Rs. 525 per day</p> <p>(ii) Other charges</p> <p>At the scale of 125% of the limits laid down under the Hospitalisation Scheme applicable to workmen employees.</p>
b) Senior Management Grade Scales IV and V and Top Executive Grade Scales VI and VII.	<p>(i) Bed Charges</p> <p>Self – Rs.900 per day</p> <p>Family – Rs.675per day</p> <p>(ii) Other charges</p> <p>At the scale of 150% of the limits laid down under the Hospitalisation Scheme applicable to workmen employees.”;</p>

9. In regulation 25 of the said regulations, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation(1), it shall be open to the Bank to provide residential accommodation to an officer on payment by the officer, on and from the 1st day of November, 2007, a sum equal to 1.20 per cent, of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less:

Provided that where the officer is provided with furniture at such residence, a further sum equal to 0.25 per cent of basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed shall be recovered by the Bank from him:

Provided further that, where such residential accommodation is provided by the bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer.”.

10. In regulation 36 of the said regulations, after sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be inserted, namely :-

“(3) With effect from the 1st day of May 2010, within the overall period of 12 months, leave may also be granted in case of hysterectomy upto a maximum of 45 days.”.

11. In regulation 41 of the said regulations, in sub-regulation (4), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

‘(a) Halting Allowance – On and from the 1st day of May, 2010, an officer in the Grades or Scales set out in column (1) of the Table below shall be entitled to ‘per diem’ Halting Allowance at the corresponding rates set out in column (2) thereof, namely:-

TABLE

Grades/Scales of officers	Major ‘A’ Class cities	Area I	Other Places
(1)	(2)		
	Rs.	Rs.	Rs.
Officers in Scale IV and above	1000	800	700
Officers in Scale I/II/III	800	700	600

Provided that in the case of officers in Scale IV and above, Halting Allowance payable per diem while on outstation work at the four metros, viz., Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai, shall be Rs.1200 and for officers in Scale I or II or III, the per diem Halting Allowance shall be Rs.1000:

Provided further that where the total period of absence is less than eight hours but more than four hours, Halting Allowance at half the above rates shall be payable.

Explanation.- For the purpose of computing Halting allowance “per diem” shall mean each period of twenty-four hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the scheduled time of departure in other cases, to the actual time of arrival and where the total period of absence is less than twenty-four hours, “per diem” shall mean a period of not less than eight hours.’.

12. In regulation 42 of the said regulations, after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

“(4) On and from the first day of May 2010, an officer on transfer shall be eligible to draw a lump sum amount for expenses connected with packing, local transportation, insuring the baggage, etc., as specified in the Table below, namely:-

“TABLE

Grade	Lump Sum
Top Executive and Senior Management	Rs.12,000
Middle Management and Junior Management	Rs.9,000”.

13. In regulation 44 of the said regulations, in sub-regulation (3), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that with effect from the 1st May 2010, an officer in Junior Management Grade Scale I while availing Leave Travel Concession shall be entitled to travel by air in the lowest fare economy class in which case the reimbursement will be the actual fare or the fare applicable to AC First Class fare by train for the distance traveled, whichever is less and the same rules shall apply to an officer in Middle Management Grade Scale II and Middle Management Grade Scale III while availing Leave Travel Concession where the distance is less than 1000 kms.”.

14. In regulation 45 of the said regulations, -

(i) in sub-regulation (1), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that there shall be no Provident Fund to Officers joining the services of the Banks on or after the 1st day of April, 2010.”;

- (ii) in sub-regulation (3), after clause (b) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely:-
- “(c) Officers who are covered under the Contributory Provident Fund Scheme who do not opt for Pension Scheme shall continue under the Contributory Provident Fund Scheme.”;
- (iii) after sub-regulation(3), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-
- “(4) The officers joining the services of the Bank on or after the 1st day of April 2010 shall be covered by a Defined Contributory Pension Scheme, where the officer shall contribute ten per cent, of pay plus Dearness Allowance and the Bank shall make the similar amount of contribution in accordance with the provisions of the Contributory Pension Scheme in accordance with New Pension Scheme notified by the Central Government vide notification of the Government of India, F.No.5/7/2003-ECB & PR dated the 22nd December, 2003, as amended from time to time.”

15. For the Schedule to the said regulations, the following Schedule shall be substituted, namely:-

“Schedule to, Bank of baroda (Officers’) Service Regulations, 1979.[See sub-regulation (2) of regulation 23]
With effect from the 1st day of November, 2007, an officer shall be eligible for the Special Area Allowance till such time they are withdrawn or modified either wholly or partially, as specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sr. No.	Area	Allowances (Rs.)	
		Pay below Rs. 14,700/-	Pay above Rs. 14,700/-
1	2	3	4
1.	Mizoram		
	(a) Chimgtuipui District of Mizoram and areas beyond 25 kms. from Lunglei Town in Lunglei District of Mizoram.	2000	2600
	(b) Throughout Lunglei District excluding areas beyond 25 kms. from Lunglei town of Mizoram.	1600	2100
	(c) Throughout Aizawl District of Mizoram	1200	1500
2.	Nagaland	1600	2100
3.	Andaman and Nicobar Islands		
	(a) North Andaman, Middle Andamans, Little Andaman, Nicobar and Narcondum Islands	2000	2600
	(b) South Andaman (including Port Blair)	1600	2100
4.	Sikkim	2000	2600
5.	Lakshadweep Islands	2000	2600
6.	Assam	320	400
7.	Meghalaya	320	400
8.	Tripura		
	(a) Difficult areas of Tripura	1600	2100
	(b) Throughout Tripura except difficult areas.	1200	1500
9.	Manipur	1200	1500
10.	Arunachal Pradesh		
	(a) Difficult areas of Arunachal Pradesh	2000	2600
	(b) Throughout Arunachal Pradesh other than difficult areas.	1600	2100
11.	Jammu and Kashmir		
	(a) Kathua District: Niabat Bani, Lohi, Malhar and Machhodi	2000	2600
	(b) Udhampur District:		
	(i) Dudu Basantgarh, Lander Bhamag Illaqa, other than those included in Part 2(b).	2000	2600
	(ii) Areas upto Goel from Kamban Side and areas upto Arnas from Keasi side in Tehsil Mohre.	1600	2100

Sr. No.	Area	Allowances (Rs.)	
		Pay below Rs. 14,700/-	Pay above Rs. 14,700/-
1	2	3	4
	(c) Doda District: Illaquas of Padder and Niabat Nowgam in Kishtwar Tehsil	2000	2600
	(d) Leh District : All places in the District	2000	2600
	(e) Barmulla District		
	(i) Entire Gurez-Nirabat, Tangdar Sub-Division and KeranIllaqua	2000	2600
	(ii) Matchill	1600	2100
	(f) Poonch and Rajouri District : Areas in Poonch and Rajouri District excluding the towns of Poonch and Rajouri and Sunderbani and other urban areas in the two Districts.	1200	1500
	(g) Areas not included in items (a) to (f) above, but which are within the distance of 8 kms. from the line of Actual Control or at places which may be declared as qualifying for border allowance from time-to-time by the State Government for their own staff.	1200	1500
12.	Himachal Pradesh		
	(a) Chamba District		
	(i) Pangi Tehsil, Bharmour Tehsil, Panchayats : Badgaun, Bajol, Deol Kugti, Nayagam and Tundah, Villages: Ghatu of Gram Panchayat Jagat, Kanarsi of Gram Panchayat Chauhata	2000	2600
	(ii) Bharmour Tehsil, excluding Panchayats and Villages included in item (i) above.	1600	2100
	(iii) Jhandru Panchayat in Bhatiyat Tehsil, Churah Tehsil, Dalhousie Town (including Banikhet proper).	1200	1500
	(b) Kinnaur District:		
	(i) Asrang, Chitkul and Hango Kuno/ Charang Panchayats, 15/ 20 Area comprising the Gram Panchayats of Chhota Khamba, Nathpa and Rup, Pooh Sub-Division, excluding the Panchayat Areas specified above.	2000	2600
	(ii) Entire District other than Areas included in (a) above.	1600	2100
	(c) Kullu District:		
	(i) 15/20 Area of Nirmand Tehsil, comprising the Gram Panchayats of Kharga, Kushwar and Sarga.	2000	2600
	(ii) Outer-Saraj (excluding villages of Jakat-Khana and Burrow in Nirmand Tehsil) and entire District excluding outer Seraj area and pargana of Pandrabis but including villages Jagat-Khana and Burrow of Tehsil Nirmand).	1200	1500
	(d) Lahaul and Spiti District : Entire area of Lahaul and Spiti	2000	2600
	(e) Shimla District :		
	(i) 15/20 area of Rampur Tehsil comprising of Panchayats of Koot, Labana-Sadana, Sarpara and Chadi-Branda.	2000	2600
	(ii) Dora-Kawar Tehsil, Gram Panchayat of Darkali in Rampur, Kashapath Tehsil and Munish, Ghor Chaibis of Pargana Sarahan.	1600	2100
	(iii) Chopal Tehsil and Ghoris, Panjgaon, Patsnau, Naubis	1200	1500

Sr. No.	Area	Allowances (Rs.)	
		Pay below Rs. 14,700/-	Pay above Rs. 14,700/-
1	2	3	4
	and Teen Koti of Pargana Sarahan, Deothi Gram Panchayat of Taklesh Area, Pargana Barabis, Kasba Rampur and Ghorl Nog of Pargana Rampur of Rampur Tehsil, Simla Town and its suburbs (Dhalli, Jatog, Kasumpti, Mashobra, Taradevi and Tutu).		
	(f) Kangra District:		
	(i) Areas of Bara Bhargal and Chhota Bhargal	1600	2100
	(ii) Dharamshala Town of Kangra District and the following offices located outside the Municipal limits but included in Dharamshala Town-Women's ITI, Dari, Mechanical Workshop, Ramnagar, Child Welfare and Town and Country Planning Offices, Sakoh, CRSF Office at lower Sakoh, Kangra Milk Supply Scheme, Dugiar, HRTC Workshop, Sadher, Zonal Malaria Office, Dari, Forest Corporation Office, Shamnagar, Tea Factory, Dari, I.P.H. Sub-Division, Dan, Settlement Office, Shamnagar, Hinwa Project, Shamnagar. Palampur Town of Kangra District including HPKV Campus at Palampur and the following offices located outside its municipal limits but included in Palampur Town – H.P. Krishi Vishwavidyalaya Campus, Cattle Development Office/Jersey Farm, Banuri, Sericulture Office/Indo-German Agriculture Workshop/HPPWD Division, Bundla, Electrical Sub-Division, Lohna, D.P.O. Corporation, Bundla, Electrical HESEE Division, Ghuggar.	1200	1500
	(g) Mandi District:		
	Chhuhar Valley of Jogindernagar Tehsil, Panchayats in thunag Tehsil-of Bagraa, Chatri, Chhotdhar, Garagushain, Gattoo, Garyas, Janjehli, Jaryar, Johar, Kalhani, Kalwan, Kholanal, Loth, Silibagi, Somachan, Thachdhar, Tachi, Thana, Panchayats of Dharampur Block- Binga, Kamlah, Saklana, Tanyar and Tarakholah, Panchayats of Karsog Tehsil – Balidhar, Bagra, Gopalpur, Khajol, Mahog, Mehudi, Manj, Pekhi, Sainj, Sarahan and Teban, Panchayats of Sundernagar Tehsil – Bohi, Batwara, Dhanyara, Paura-Kothi, Seri and Shoja.	1200	1500
	(h) Sirmaur District:		
	Panchayats of Bani, Bakhali (Pachhad Tehsil), BharogBheneri (Paonta Tehsil), Birla (Nahan Tehsil), Dibber (Pachhad Tehsil) and Thana Kasoga (Nahan Tehsil) and Thansgiri Tract.	1200	1500
	(i) Solan District :		
	Mangal Panchayat.	1200	1500
	(j) Remaining areas of Himachal Pradesh not included in items (a) to (i) above.	320	400
13.	Uttarakhand Areas under Chamoli, Pithoragarh, Uttarkashi, Rudraprayag and Champavat Districts.	2000	2600"

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Regulations which have been given retrospective effect are as per the agreed terms and conditions of the Joint Notes signed between the Indian Banks' Association on behalf of member banks on the basis of specific mandate given by the respective banks in this regard and apex level officers' associations of the Banks. Therefore, interests of no person shall be adversely affected by such retrospective effect.

K. B. GUPTA, General Manager Head (Hr Operations)

[ADVT.-III/4/Exty./327/17]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India on _____ and subsequently amended *vide* following notifications, namely:-

1. No. _____, dated the _____, day of _____
- 2.